Realisation of Misuse Charges of Residential Properties

7435. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) what are the particulars of lessees who have been allowed to pay less than normal/standard misuse charges in contravention of lease arrangements;

(b) whether the L&DO has any policy, guidelines or criteria to deal with cases of comercial misuse of residential properties by tenants of lessees where such tenants are not paying misuse charges and the entire burden for payment of progressively rising misuse charges falls on house owners who neither have the capacity nor the resources to pay these charges, if so, the details thereof; and

(c) what are the remedies available to such lessees who have already initiated legal proceedings against misuse by such tenants and who are still being asked to pay misuse charges under threat of re-entry even before judgements in the legal cases against the misuser?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) According to the report of Land and Development Officer, no statistical data is maintained regarding the particulars of lessees who have been allowed to pay less than the normal/standard misuse charges in contravention of lease arrangements.

(b) No, Sir. The privity of contract is between the lessor and the lessee and not between the lessor and the tenants of the lessee.

(c) Under the terms of the lease where the misuse is caused or suffered to be caused by the tenants of the lessees, the responsibility for removal of the misuse rests with the lessee who can resort to judicial proceedings in a court of law.

उचित दर की नई दुकाने खोलना

7436. **श्री धर्मदास शास्त्री :** नागरिक पूर्ति मंत्री उचित दर की दुकानों पर यूनिटों की संख्या के बारे में 29 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5671 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में कितनी उचित दर की दुकानें आंवटित की गई जिनमें अभी भी निर्धारित 4000 यूनिटों से कम यूनिट हैं ;

(ख) उपर्युक्त दुकानों में नये राशन कार्डों को संलग्न करने के स्थान पर नजदीक के उचित दर दुकानों को निर्धारित यूनिटों के बकाया यूनिटों को स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां उचित दर दुकानें अधिसूचित की गई थीं परन्तु जिनके लिए कोई आवेदन-पत्र नहीं मिला और इनके नोटिस, कब जारी किए गये तथा ये कहां-कहां लगाए गए और क्या समाचार-पत्रों में भी तदर्थ विज्ञापन दिया गया :

(घ) उचित दर दुकानों के ऐसे कितने दुकानदार हैं जिन्होंने निर्धारित यूनिट संख्या उपलब्ध न होने और पर्याप्त सामयिक सप्लाई न होने के विरोध स्वरूप दुकानें बन्द करने का नोटिस दिया है; और

(ङ) विभाग नए दुकानों को निर्धारित यूनिट संख्या उपलब्ध कराने और पर्याप्त सामयिक सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ): (क) हाल ही में दिल्ली में खोली